अप्रैल में 119.27 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही, पिछले साल के मुकाबले 41 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली , 2 मई (ए)। कोरोना की दूसरी लहर का कारोबारी गतिविधियों पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। इसकी गवाही देश में बिजली खपत के आंकड़े दे रहे हैं। बिजली मंत्रालय के डाटा के अनुसार, अप्रैल में देश में 119.27 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले इसमें 41 प्रतिशत का उछाल रहा है। इस साल अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा बिजली खपत का भी नया रिकॉर्ड बना है। पिछले महीने एक दिन में सबसे ज्यादा 182.55 गीगावाट बिजली की खपत रही है। यह पिछले साल अप्रैल के रिकॉर्ड 132.73 गीगावाट से 38 प्रतिशत ज्यादा है। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के कारण अधिकांश कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी। इस कारण 84.55 बिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई थी। जबकि अप्रैल 2019 में 110.11 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही थी। इसी तरह से एक दिन की सबसे ज्यादा खपत भी 2019 के मुकाबले 2020 में कम रही थी। अप्रैल 2019 में एक दिन की सबसे ज्यादा खपत 176.81 गीगावाट रही थी। जानकारों का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां थमने के कारण बिजली की खपत में कमी रही थी। इस कारण इस साल अप्रैल में खपत और डिमांड में अच्छी ग्रोथ रही है। जानकारों के मुताबिक, इस साल बिजली खपत की ग्रोथ बताती है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्तर पर बिजली डिमांड में रिकवरी हो रही है। हालांकि, जानकार चेतावनी देते हैं कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लगाए जा रहे लॉकडाउन का आने वाले महीनों में बिजली खपत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पिछले साल 6 महीने बाद सितंबर में बिजली खपत में 4.6 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई थी। इसके बाद अक्टूबर में 11.6 प्रतिशत की ग्रोथ रही थी। हालांकि, सर्दियां शुरू होने के कारण नवंबर में बिजली खपत की ग्रोथ घटकर 3.12 प्रतिशत रह गई थी। दिसंबर में बिजली खपत में बढ़ोतरी के कारण 4.5 प्रतिशत की ग्रोथ रही थी। जबकि जनवरी 2021 में 4.4 प्रतिशत की ग्रोथ रही थी।

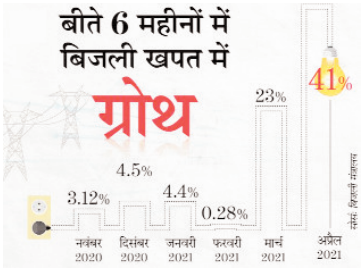

मार्च 2021 में 23 प्रतिशत की ग्रोथ रही: इस साल फरवरी में बिजली खपत में 0.28 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ रही थी। फरवरी 2020 की 103.81 बिलियन यूनिट के मुकाबले इस साल फरवरी में 104.11 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही। 2020 के लीप ईयर होने के कारण फरवरी में बिजली की खपत ज्यादा रही थी। हालांकि, इस साल मार्च में बिजली की खपत में 23 प्रतिशत की ग्रोथ रही। मार्च 2020 की 98.95 बिलियन यूनिट के मुकाबले इस साल मार्च में 121.51 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली खपत में 1 प्रतिशत की गिरावट रही है। 2019-20 की 1284.44 बिलियन यूनिट के मुकाबले 2020-21 में 1271.54 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही।

स्पाइसजेट ने पायलट-केबिन क्रू की 90 प्रतिशत तक सैलरी रोकी

नई दिल्ली, 2 मई (ए)। कोरोना संक्रमण से एविएशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब कोरोना की दूसरी लहर का असर भी एविएशन सेक्टर पर दिखने लगा है। कोरोना के कारण लोग हवाई सफर करने से बच रहे हैं। इससे एयरलाइंस के पास कैश की कमी होने लगी है। देश की प्रमुख निजी एयरलाइंस स्पाइसजेट के पास कैश की किल्लत हो गई है। यही कारण है कि स्पाइसजेट ने अप्रैल महीने की सैलरी में 90 प्रतिशत तक की कटौती की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्पाइसजेट ने लोडर, ड्राइवर समेत जूनियर स्तर के कर्मचारियों को पूरी सैलरी का भुगतान किया है। लेकिन ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू, कमर्शियल स्टाफ और पायलट्स को अप्रैल महीने में 10-50 प्रतिशत सैलरी का ही भुगतान किया है। वहीं, एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह ने अपनी पूरी सैलरी छोड़ दी है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि हालात सामान्य होने पर बकाया सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रेसीडेंट ऑपरेशंस की ओर से शनिवार को पायलट्स को भेजे पत्र में कहा गया है कि फरवरी में घरेलू एयरलाइंस में हवाई यात्रियों की रोजाना संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई थी। इससे लग रहा था कि एविएशन सेक्टर में रिकवरी हो रही है। लेकिन अब यात्रियों की संख्या गिरकर 1.30 लाख रोजाना पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए स्पाइसजेट परिवार के हित में एक बार फिर कड़े आर्थिक उपाय लागू किए गए हैं। ज्यादा पेय ग्रेड वालों की सैलरी 10-90 प्रतिशत तक रोकी गई है। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए यह अस्थायी उपाय किए गए हैं।

अप्रैल में देश का निर्यात बढ़कर 2.23 लाख करोड़ पर पहुंचा, पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ग्रोथ

नई दिल्ली, 2 मई (ए)। अप्रैल में देश से निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी प्रारंभिक डाटा के मुताबिक, अप्रैल में देश का कुल निर्यात 30.21 बिलियन डॉलर करीब 2.23 लाख करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के 10.17 बिलियन डॉलर करीब 75 हजार करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले इसमें 3 गुना की ग्रोथ रही है।

3.36 लाख करोड़ रुपए का आयात: निर्यात की तर्ज पर अप्रैल में आयात में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में देश का कुल आयात 45.45 बिलियन डॉलर करीब 3.36 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल अप्रैल में 17.09 बिलियन डॉलर करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए का आयात हुआ था। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल में भारत शुद्ध रूप से आयातक रहा है। अप्रैल में देश का व्यापार घाटा 15.24 बिलियन डॉलर करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, अप्रैल में व्यापार घाटा 120.34 प्रतिशत रहा है। अप्रैल 2020 में देश का व्यापार घाटा 6.92 बिलियन डॉलर करीब 51 हजार करोड़ रुपए रहा था।

जेम्स एंड ज्वैलरी, जूट, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, लैदर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑयल मील्स, काजू, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स। आने वाले महीनों में देश में कोल इंपोर्ट में कमी आ सकती है। इसके पीछे विभिन्न कारण हैं। इसमें कोविड का माहौल, कोयले का ज्यादा स्टॉक और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतें शामिल हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मजूंक्शन टाटा स्टील और ब्रूहू की संयुक्त बी-2-बी ई-कॉमर्स कंपनी है। यह कोल और स्टील से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है।

वित्त वर्ष 2021 में घटा कोल इंपोर्ट: मजूंक्शन के प्रारंभिक डाटा के मुताबिक, इसके मुताबिक, बीमा की रकम लेने के लिए दावेदार को सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा। कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावे के मामले में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देना जरूरी होता है। इसी तरह बीमा की रकम की गणना मृत ईपीएफओ कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की सैलरी के आधार पर किया जाता है। इसके तहत पिछले 1 साल में जो बेसिक सैलरी और डीए होगा, उससे 30 गुना ज्यादा क्लेम मिलेगा जो अधिकतम 7 लाख रुपए तक ही होगा। अगर आपने 1 साल के अंदर संस्थान बदल दिया है तो ऐसी स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा। ईपीएफओ रिटायरमेंट सेविंग के 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का प्रबंधन करता है। 15 मार्च को वित्त मंत्रालय ने निवेश पैटर्न में बदलाव किया था। हालांकि यह बदलाव सिर्फ गैर सरकारी भविष्य निधि के लिए है जो अपने कामगारों की रिटायरमेंट बचत का प्रबंधन इनहाउस करते रहते हैं। दरअसल पीएफ के तहत जो भी रकम ईपीएफओ को मिलती है, उसे जगह-जगह पर निवेश किया जाता है।

पिछले साल लॉकडाउन के कारण घटा था निर्यात

पिछले साल पूरा अप्रैल महीना कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में बीता था। इस कारण निर्यात में 60.28 प्रतिशत की गिरावट रही थी। हालांकि, इस साल मार्च में निर्यात में 60.29 प्रतिशत की ग्रोथ रही थी। मार्च 2021 में 34.45 बिलियन डॉलर करीब 2.55 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। अप्रैल 2021 में तेल आयात 10.8 बिलियन डॉलर करीब 80 हजार करोड़ रुपए रहा था। समान अवधि में 4.65 बिलियन डॉलर करीब 34 हजार करोड़ रुपए के तेल का आयात हुआ था।

वित्त वर्ष 2021 में कोल इंपोर्ट में 12.62 प्रतिशत की गिरावट रही है। वित्त वर्ष 2021 में कुल 215.92 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट हुआ है। जबकि वित्त वर्ष 2020 में 247.10 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट हुआ था। बंदरगाहों और शिपिंग कंपनियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह डाटा जारी किया गया है।

कोविशील्ड का भारत से बाहर उत्पादन करने की योजना बना रहा सीरम इंस्टीट्यूट, जल्द हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली, 2 मई (ए)। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन का उत्पादन भारत से बाहर करने की योजना बना रहा है। कच्चे माल की आपूर्ति में दिक्कत के चलते कंपनी यह योजना बना रही है। एक अखबार से बातचीत में एसआईआई की सीईओ अदार पूनावाला ने यह बात कही है। एसआईआई एस्ट्राजेनेका की कोवीशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करती है।

अदार पूनावाला का कहना है कि भारत से बाहर उत्पादन की घोषणा जल्द हो सकती है। पूनावाला ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई के बाद अपना उत्पादन 100 मिलियन डोज तक बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे पहले मई के अंत तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की टाइमलाइन तय की गई थी। इस समय देश के कई राज्य कोविड वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। अदार पूनावाला का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 6 महीने में सीरम इंस्टीट्यूट की उत्पादन क्षमता 2.5 बिलियन से 3 बिलियन डोज सालाना हो जाएगी। पूनावाला ने कहा कि भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगने पहले ही वह लंदन पहुंच गए थे। देश में कोरोना के केस बढ़ने के कारण ऑक्सीजन, दवाएं और अन्य जरूरी उपकरणों की कमी हो गई है। सरकार को यह सामान विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में कोरोनावायरस 3-5 मई के दौरान पीक पर पहुंच सकता है।

देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को यहां रिकॉर्ड 4 लाख 1 हजार 911 नए संक्रमितों की पहचान हुई। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है।

अब डेथ क्लेम में अधिकतम 7 लाख मिलेगा, अभी तक यह 6 लाख रुपए था

मुंबई, 2 मई (ए)। कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अब मौत के मामले में बीमा का दावा किया गया है तो उसमें 7 लाख रुपए की रकम मिलेगी। पहले यह 6 लाख रुपए थी।

इसका फायदा ईपीएफओ के कम से कम 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। इसी तरह अब किसी खाताधारक की मौत पर कम से कम बीमा राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 2 लाख रुपए थी। यानी कम से कम और अधिकतम दावे की रकम को बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट ने सितंबर 2020 की बैठक में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया था। श्रम मंत्रालय ने अब जाकर इसे मंजूरी दी है। उसका यह आदेश एंप्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस से संबंधित है।

मृतक के परिवार को मिलेगा बीमा का फायदा: अगर किसी सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। वैसे तो ईडीएलआई के लाभार्थियों की संख्या ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के बराबर नहीं है। ईडीएलआई के तहत करीब 20 लाख ही ग्राहक हैं। हर ईडीएलआई सब्सक्राइबर ईपीएफ सब्सक्राइबर होता है लेकिन हर ईपीएफ सब्सक्राइबर ईडीएलआई सब्सक्राइबर नहीं होता है। इसलिए दोनों ही संख्या में काफी फर्क है।

काफी अहम होती है रकम: नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड की रकम काफी अहम होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले कर्मचारियों को खाते पर ब्याज समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक सुविधा बीमा की है। इसके मुताबिक, अगर ईपीएफओ के एक एक्टिव कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत होती है तो उसके नॉमिनी को बीमा की रकम का एकमुश्त पेमेंट किया जाता है।

ईपीएफओ के सदस्य खुद इस योजना से जुड़ जाते हैं। इस बीमा के लिए कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है। कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी हैं।

एसबीआई ने फिर घटाया होम लोन पर ब्याज: मिलता रहेगा होम लोन

मुंबइ, 2 मई (ए)। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज की दरें फिर घटा दी हैं। 30 लाख रुपए तक का होम लोन अब 6.70 प्रतिशत ब्याज की दर से मिलेगा। अगर होम लोन 30 लाख से ज्यादा है को फिर आपको 6.95 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। बैंक ने कहा कि 6.95 प्रतिशत की दर 30 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर लागू रहेगी। अगर लोन 75 लाख से ज्यादा है तो फिर ब्याज दर बढ़ कर 7.05 प्रतिशत हो जाएगी। अगर आपइसके बैंकिंग ऐप योनो से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 बीपीएस की छूट और मिलेगी। एसबीआई के रिटेल और डिजिटल बैंकिंग के प्रबंध निदेशक (एमडी) सी.एस. शेट्टी ने कहा कि होम फाइनेंस में एसबीआई एक मार्केट लीडर है और होम लोन मार्केट में ग्राहकों के बेंचमार्क को देखते हुए ब्याज दरों को कम रखा जाता है। हमें विश्वास है कि यह नया फैसला होम लोन लेने वालों और रियल इस्टेट इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छा होगा।

घरेलू शेयर बाजार में उठा-पटक जारी रह सकती है

नई दिल्ली, 2 मई (ए)। घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते बहुत उठा-पटक हुई। सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार ने अच्छी की थी। एनएसई का निफ्टी 15,000 पॉइंट का लेवल छूने में कामयाब रहा। लेकिन इंडेक्स अपनी बढ़त को कायम नहीं रख पाया। शुक्रवार को ऊपरी स्तरों पर भारी बिकवाली देखी गई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। अमेरिका भारत से अपने नागरिकों को लौटने और यहां से उड़ानें बंद करने की बात कर रहा है। कोविड के बढ़ते मामले घरेलू बाजार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उसको अगले हफ्ते विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार होगा। घरेलू शेयर बाजार में उठा-पटक अगले हफ्ते भी हो सकती है। लेकिन एनएसई का निफ्टी 14,300 से 14,900 के दायरे में रह सकता है। जहां तक बैंकिंग निफ्टी की बात है तो इसको 32,000 के आस-पास खरीदारी का मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। ये बातें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन तापड़िया ने कही हैं। चंदन के मुताबिक निफ्टी ने 14,150 से 15,050 तक का सफर चंद दिनों में तय किया है जो अच्छी बात है। बिकवाली ऊपर के स्तरों पर ही देखने को मिली है, जो गिरावट में खरीदारी होने का संकेत है। बाजार में निराशा के बीच फार्मा और कुछ टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छी खरीदारी निकली। अगले हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स सीमित दायरे में रह सकते हैं लेकिन फार्मा, मेटल और टेक्नोलॉजी स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मासिक बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। इससे ऑटो कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। बाजार में अभी जो माहौल है उसमें खुदरा निवेशकों को ट्रेडिंग से ज्यादा ध्यान लंबे समय के लिए निवेश करने पर देना चाहिए। बाजार में कुछ समय के लिए उठा-पटक रह सकती है लेकिन लंबी अवधि में रुझान सकारात्मक रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को मुश्किलों के बावजूद शेयर बाजार में बने रहना चाहिए। जहां तक बंगाल के चुनावी नतीजों की बात है तो एग्जिट पोल काटे की टक्कर दिखा रहा है। यहां के चुनावी नतीजों पर देश-दुनिया की नजर है। कहीं न कहीं ये नतीजे कॉरपोरेट इंडिया को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तापड़िया के मुताबिक, वहां सता परिवर्तन होने पर शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान बन सकता है। छोटे निवेशकों को अगले 2-3 सालों के लिए सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक सेक्टरों की बात है तो निवेश के लिए प्राइवेट बैंक, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, दिगज कंजम्पशन कंपनियों के शेयर चुने जा सकते हैं।

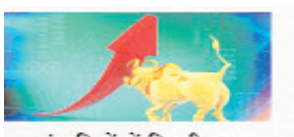

चंद दिनों में निफ्टी का 14,150 से 15,050 तक का सफर सुखद, गिरावट में खरीदारी होने का संकेत है ऊपर के स्तरों पर बिकवाली

खुदरा निवेशकों को ट्रेडिंग से बचना चाहिए, 2-3 बरसों के लिए सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए

एसबीआई के खाताधारकों को राहत: केवायसी डिटेल अपडेट नहीं होने पर 31 मई तक फीज नहीं होगा खाता

नई दिल्ली , 2 मई (ए)। अगर आपका बचत खाता देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में है तो आपके लिए एक राहत वाली खबर है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को नो योर कस्टमर डिटेल अपडेट कराने के लिए शाखाओं में नहीं बुलाने का फैसला किया है। एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को पत्र भेज कर इसके बारे में बताया है। बैंक ने अपनी शाखाओं से यह भी कहा है कि अगर ग्राहक अपना केवायसी डिटेल अपडेट नहीं करा पाएं तो उनका खाता आंशिक रूप से फ्रीज न करें। उसने शाखाओं से 31 मई तक इससे परहेज करने के लिए कहा है। एसबीआई ने शाखाओं को भेजे लेटर में लिखा है कि जिन ग्राहकों का केवायसी डिटेल अपडेट होना बाकी है, बैंक उनके रिकॉर्ड डाक या रजिस्टर्ड इमेल आईडी से मिले जरूरी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपडेट कर सकते हैं। बैंक ने यह कदम कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए एक ट्वीट के बाद उठाया है। वित्त मंत्री ने अपने मंत्रालय के संबंधित विभागों को इस बारे में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था। सभी बैंक आमतौर पर कम जोखिम की कैटेगरी वाले ग्राहकों से हर 10 साल में केवायसी अपडेट कराने के लिए कहते हैं। मध्यम जोखिम वाली कैटेगरी में आने वाले ग्राहकों से अपना डिटेल हर आठ साल में अपडेट करने के लिए कहा जाता है। ज्यादा जोखिम की कैटेगरी वाले ग्राहकों से हर दो साल में केवायसी अपडेट कराने के लिए कहा जाता है। किस ग्राहक को किस रिस्क कैटेगरी में डालना है।